क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 290, मंगलवार, 20 नवम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

क्राइम: एएमयू छात्र को कैंपस में दिनदहाड़े मारी गोली, हड़कंप

अलीगढ़, एजेंसी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सोमवार को दिनदहाड़े एक छात्र को सुलेमान हॉल के पास गोली मार दी, जिससे विवि कैम्पस में हड़कंप मच गया। फायरिंग की आवाज से छात्रों में अफ्रातफ्री मच गई। आनन फानन में घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आज़मगढ़ निवासी छात्र यासीन एएमयू से पीजी डिप्लोमा कर रहा है। सोमवार को सुलेमान हॉल के पास कैंटीन में खाना खा रहा था। छात्र ने बताया कि इसी दौरान दो बाइक पर चार-पांच छात्र आए और गाली-गलौज शुरू कर दिया, जब विरोध किया तो मारपीट करने के साथ ही फायरिंग कर दी, एक गोली यासीन के पैर में लगी है। दिनदहाड़े हुई फ़ायरिंग की घटना कैंटीन और आसपास के इलाके में खलबली मच गई। विवि सुरक्षा कर्मियों और साथियों ने घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।

अयोध्या पंचकोसी परिक्रमा में शामिल लाखों रामभक्तों को धर्मसभा में आने का दिया न्योता

अयोध्या, एजेंसी। अयोध्या में 25 नवंबर को रामजन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए होने वाली धर्मसभा को सफ्ल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। सोमवार को पंचकोसी परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं के बीच आमंत्रण पत्र वितरित कर जनसभा में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर आमंत्रण पत्र का वितरण अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव , भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ. चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा व महानगर प्रभारी हरीश श्रीवास्तव , हरभजन गौड ,मंडल महामंत्री लक्ष्मण वर्मा, अभिषेक अग्रवाल मौजूद रहे। अयोध्या में धर्मसभा के लिए भाजपा अब खुलकर सामने आ गयी है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल भी जुटे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ लाखों श्रद्धालुओं को पत्रक बांटा है। 15 लाख पत्रक बाटने का दावा किया गया है। 25 नवंबर को अयोध्या में भारी भीड़ होने की उम्मीद है । 24 नवंबर को ही शिव सैनिकों के साथ उद्धव ठाकरे भी अयोध्या पहुंच जाएंगे।

प्रेस से बात नहीं करते मोदी : राहुल

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेस से बात नहीं करने का आरोप लगाया और तंज किया कि उन्हें अपने 56 इंच का सीना लेकर प्रेस कांफ्रेंस करनी चाहिए। गांधी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वह बराबर मीडिया से बात करते हैं और उनके हर सवालों का जवाब देते हैं लेकिन प्रधानमंत्री प्रेस से बात नहीं करते हैं। उन्होंने पहले भी कई बार आरोप लगाया, मोदी प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से डरते हैं इसलिए वह प्रेस से बात नहीं करते हैं। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया छत्तीसगढ़ में मैंने प्रेस के सदस्यों से बातचीत की। उस बातचीत का एक छोटा वीडियो देखें। एक दिन मुझे यकीन है कि हमारे प्रधानमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही श्री गांधी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वह छत्तीसगढ़ में अपने चुनावी कार्यक्रम के बीच पाकारों से बात कर रहे हैं।

नई दिल्ली : इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में अभूतपूर्व योगदान के लिए सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को सुमित्रा चरत राय अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अमृतसर में धमाके के बाद दिल्ली-UP में हाई अलर्ट, सुरक्षा के लिए 20 कंपनियां तैनात

नई दिल्ली लखनऊ। अमृतसर में हमले के बाद दिल्ली और यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और चाक-चौबंद बनाने के लिए सुरक्षाबलों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। इन्हें खासतौर से भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त करने को कहा गया है। यूपी के अयोध्या, मथुरा और वाराणसी समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सघन जांच की जा रही है। अमृतसर की घटना के बाद दिल्ली स्थित पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। इसके बाद बुराड़ी इलाके में स्थित संत निरंकारी आश्रम की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तैनाती की गई है।

14 जगहों पर 'पराक्रम ' वाहन तैनात :

सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के करने व संदिग्धों पर पैनी नजर रखने के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो वाहन दस्ते 'पराक्रम' की 14 अलग-अलग स्थानों पर तैनाती कर दी गई है। उधर, यूपी के एडीजी कानून-व्यवस्था आनंद कुमार ने धार्मिक स्थलों व प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाने, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जांच कराने तथा अंतरराज्यीय सीमाओं में सघन चेकिंग कराने के निर्देश दिए हैं।

मंदिर निर्माण के लिए जनभावना का आदर करते हुए शीघ्र फैसला दे सुप्रीम कोर्ट : संघ

अयोध्या, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने सोमवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन किया। दर्शन-पूजन करने के बाद श्री जोशी ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी प्रार्थना है कि टेंट में यह उनकी ओर से रामलला का अंतिम दर्शन हो।

ऐसी परिस्थितियां बने कि अयोध्या में दोबारा रामलला का दर्शन भव्य मंदिर में हो।

अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाली धर्मसभा को सफल बनाने के लिये तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे श्री जोशी ने कहा कि साधु-संतों के आह्वान पर अयोध्या में धर्मसभा आयोजित हो रही है।

रामभक्त व हिन्दू होने के कारण हम सभी धर्म सभा में सम्मिलित होंगे। अयोध्या में रामभक्तों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा।

धर्मसभा के माध्यम से राम मंदिर निर्माण का दोबारा संकल्प होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से नहीं न्यायालय से अपील है कि हिंदुओं की जन भावना का आदर करते हुए शीघ्र फैसला दे।

केंद्र सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पहल करे:भैयाजी जोशी

मंदिर निर्माण के लिये कानून बनाने के सवाल पर श्री जोशी ने कहा कि सोमनाथ का मामला भिन्न था। अब परिस्थितियां बदली हैं। केंद्र सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पहल करे।

कानून बनाना या न बनाना सत्ता में बैठे नेताओं का काम है। इस दौरान श्री जोशी के साथ संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, सह सरकार्यवाह हसबोले दत्तात्रेय, क्षेत्र कार्यवाह राम कुमार वर्मा, प्रांत प्रचारक कौशल किशोर, सह प्रांत कार्यवाह डा. अनिल मिश्र व डा. प्रशांत भाटिया भी मौजूद रहे।

यूपी में 'मुर्दे' का बनाया मैरिज सर्टिफिकेट, जानें ज़्या है पूरा मामला

लखनऊ, एजेंसी। साल 2017 में जिस युवक के विवाह का पंजीकरण कर प्रमाणपत्र जारी किया गया, उसकी वर्ष 2016 में ही मौत हो चुकी थी। आरटीआई के जरिए इसका खुलासा होने पर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय के होश उड़ गए।

जांच हुई तो पता चला कि 'आधार' से जुड़ी विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में इस तरह के फर्जीवाड़े की पूरी गुंजाइश मौजूद है। इस कारण के बाद अब नियमावली में बदलाव पर विचार शुरू हो गया है।

आरटीआई में महिला ने उठाए सवाल:

महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय से आरटीआई से मांगी गई सूचना में एक महिला ने पूछा है कि उसके बेटे का साल 2016 में ही निधन हो गया था तो साल 2017 में उसके विवाह का पंजीकरण प्रमाणपत्र कैसे जारी हो गया? इस स्वत: जेनरेटेड विवाह प्रमाणपत्र में महिला के बेटे की शादी 2013 में होने की बात कही गई है। इस महिला का आरोप है कि सम्पत्ति के लालच में उसके मृत बेटे के विवाह का पंजीकरण कराया गया है।

साल 2017 में ही बनी थी नियमावली

इस प्रकरण से विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बना देने के दावे के साथ बनाई गई बहुप्रचारित नियमावली पर सवाल उठने लगे हैं। यह भी एक विसंगति ही है कि विवाह का पंजीकरण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग करता है, जबकि विवाह की नियमावली महिला एवं बाल विकास विभाग ने बनाई है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के नाम से जानी जाती है।

यह नियमावली बनने से पहले प्रदेश में दो अलग-अलग नियमावली से विवाह पंजीकरण हो रहा था। पहला हिन्दू मैरेज एक्ट और दूसरा स्पेशल मैरेज एक्ट। साल 2017 की नियमावली में अनिवार्य विवाह पंजीकरण का प्रावधान भी किया गया है। विवाह पंजीकरण अधिकारी का दायित्व स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारी को ही दिया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि विवाह का पंजीकरण न होने से प्रभावित व्यक्ति खासकर महिलाएं साक्ष्य के अभाव के कारण अपने कानूनी अधिकार से वंचित रह जाती हैं। अनिवार्य विवाह पंजीकरण से राज्य में बाल विवाह भी रोका जा सकेगा।

आनलाइन प्रक्रिया में है यह प्रावधान

नियमावली में आनलाइन आवेदन की जिस प्रक्रिया में यह गड़बड़ी सामने आई है, वह 'आधार' आधारित है। इसमें यह प्रावधान है कि जहां विवाह के पक्षकारों के आधार कार्ड के साथ उनके मोबाइल नंबर जुड़े हैं, वहां पक्षकारों द्वारा दी गई सूचनाओं के संबंध में आधार कार्ड के सत्यापन के बाद विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वत: ही आनलाइन जनरेट हो जाएगा, जिसका प्रिंटआउट आवेदक स्वयं ही प्राप्त कर सकेंगे।

बिहार में है यह व्यवस्था

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार में विवाह पंजीकरण की व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत प्रधान और शहरी क्षेत्र में सभासद को जवाबदेह बनाया गया है।

अनिवार्य पंजीकरण में भी इन जन प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय की गई है। इससे विवाह पंजीकरण में फर्जीवाड़े की संभावना कम हो जाती है।

शासन के संज्ञान में है मामला

उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं निबंधन अधिकारी संघ के अध्यक्ष वीके उपाध्याय ने बताया कि मोबाइल लिंक्ड आधार से जुड़ी आनलाइन विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में सामने आई खामी से शासन को अवगत करा दिया गया है। इस तरह के पंजीकरण में विभाग की कोई भूमिका ही नहीं रह जाती है, जिससे फर्जीवाड़ा रोक पाना संभव नहीं हो पाता। शासन नियमावली में बदलाव पर विचार कर रहा है।

फेरे की साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर लगा हो गई सती होने के लिए तैयार

मैनपुरी, **एजेंसी।** मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के अंगौथा में वृद्धा की जिद ने वर्षों पुरानी सती प्रथा की यादें ताजा कर दीं। पति की मौत के बाद वृद्धा सती हो रही है यह जानकारी आग की तरह फैली। सैकड़ों की संख्या में आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए थे।

ग्रामीण, परिजन, महिला को सती न होने के लिए समझा रहे थे। लेकिन वो किसी भी कीमत पर जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन पुलिस पहुंची तो महिला की जिद टूट गई। पुलिस उसे कोतवाली ले आयी। जहां समझाने के बाद उसे घर वापस भेज दिया गया। अंगौथा निवासी गोरेलाल शाक्य किसान थे। गोरेलाल की मौत हुई उनके तीन पुत्र विजय बहादुर, देवेंद्र शाक्य, अखिलेश शाक्य के अलावा पत्नी लौंगश्री का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवारीजन अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे थे। इसी बीच लौंगश्री महिलाओं के बीच से रोते हुए उठीं और सती होने का एलान कर दिया। लौंगश्री के इस एलान से हड़कंप मच गया और उन्हें मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। महिला की जिद की खबर बड़ी तेजी से फैल गई। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस समझा रही थी लेकिन महिला जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एएसपी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि जब वो नहीं मानी तो कोतवाली पुलिस उसे मौके से ले आयी थी।

पूजा की थाली सजाई, माथे पर सिंदूर का टीका लगाकर हो गई तैयार

महिला ने विरोध के बाद भी घर के अंदर जाकर शादी के समय फेरे के दौरान पहनी जाने वाली चुनरी की साड़ी पहनी। हाथों में हरी चूड़ियां पहनने के बाद उसने पूजा की थाली सजाई।

मांग में माथे से ऊपर तक सिंदूर का एक बड़ा सा टीका लगा लिया इसके बाद पूजा की थाली लेकर वो अंतिम संस्कार स्थल की ओर रवाना होने की जिद पकड़ गईं। सैकड़ों महिलाओं के बीच पूजा की थाली सामने रखकर महिला ने हाथ जोड़ लिए। जैसे ही लोग उसे समझाने पहुंचते तो वो कहने लगती तो कि यदि किसी ने उसे छूने की कोशिश की तो उसे पाप लगेगा। लोग हैरान थे और परेशान भी थे। सती होने की बात ग्रामीण भूल भी चुके थे।

आजादी के बाद मैनपुरी में नहीं हुई इस तरह की घटना

मैनपुरी की नई पीढ़ी सती प्रथा को लगभग भूल चुकी है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने इस प्रथा के खिलाफ पूरे देश में बड़ा आंदोलन चलाया। अंग्रेजी हुकूमत ने राजा राममोहन राय के आंदोलन के बाद वर्ष 1829 में कानून बनाकर देश में सती प्रथा को बंद करा दिया। हालांकि देश को आजादी मिलने के बाद 80 के दशक तक सती प्रथा की घटनाएं होती रही हैं। मैनपुरी में आजादी के बाद कोई भी घटना इस तरह की नहीं हुई। ऐसा जानकार बताते हैं।

सती से जुड़ी कई कहानियां हैं प्रचलित

सती प्रथा को लेकर पौराणिक इतिहास की कहानी प्रचलित है। देवी सती के पिता दक्ष ने उनके पति भगवान शिव का अपमान किया। इस अपमान और तिरस्कार से क्षुब्ध होकर सती आग में कूद गई थीं। भारतीय इतिहास में भी सती की अलग-अलग कहानियां हैं।

आयरन लेडी इंदिरा गांधी का अलीगढ़ से था गहरा नाता, जानें क्यों था लगाव

अलीगढ, एजेंसी। भारत की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी का अलीगढ़ से गहरा नाता रहा है। अलीगढ़ में वे कई बार जनसभा और अन्य समारोह में शिरकत करने आईं थीं। 1974 में पहले बार आयरन लेडी का आगमन अलीगढ़ जिले में हुआ था। वे अलीगढ़ में चार बार आईं और आमजन पर अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ गईं।

इंदिरा गांधी का जिले से अटूट नाता रहा है। चुनावी जनसभा, उद्घाटन समारोह और अन्य चुनावी बैठकों को संबोधित करने जिले में आईं थीं। इंदिरा गांधी पहली बार 1974 में अलीगढ़ आईं थीं। उस समय इंदिरा ने अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस और साथा चीनी मिल का उद्घाटन किया था। 1977 में कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने नुमाइश मैदान में चुनावी सभा आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। चुनावी जनसभा के बाद अलीगढ़ उनका आगमन 1978 में कांग्रेस नेता अहमद लूत खां की बेटी की शादी समारोह में हुआ था।

ट्रेन से उनको दिल्ली जाना था, लेकिन ट्रेन लेट हो गई थी वह सड़क मार्ग से दिल्ली गईं थीं। 1977 में पिसावा कुवंर देवेंद्र पाल सिंह द्वारा आयोजित कराई गई चुनावी सभा में भी इंदिरा गांधी ने हिस्सा लिया लिया था और जनमानस को संबोधित किया था। 1980 इंदिरा गांधी का अलीगढ़ में आखिरी दौरा था। इसके बाद वह अलीगढ़ नहीं आईं।

पूर्व विधायक और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विवेक बंसल ने बताया कि यह बात है 1974 की जब हम अवर लेडी फातिमा में पढ़ते थे। तब वह अलीगढ़ आईं थी। वह दोदपुर क्षेत्र में होते हुए खुली कार में बैठकर गुजरी थीं। तब स्कूली बच्चों में हम भी शामिल थे। तब सड़क के किनारे लाइन लगवाकर खड़ा किया गया था।

कागज की झंडियां फहराईं गई थीं और इंदिरा जी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया था। आयरन लेडी के समय में भारत प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी रहा है। देश को तमाम ख्याति उन्होंने ही दिलवाई हैं।

1983 में पूर्व सांसद ने की थी मुलाकात : सिंह

पूर्व सांसद चौधरी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उनके भीतर भारत को प्रसिद्धि दिलाना व विकास के पथ पर ले जाने का विजन था।

भारत की ऐसी महिला थीं जो हमेशा से आर्थिक व मूलभूत सुविधाओं के विकास पर जोर देती थीं। बताया कि 1983 में कांग्रेस का यूथ जिलाध्यक्ष रहते हुए दिल्ली में इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात हुई थी। कहा कि ननौरा पावर प्लांट समेत वेस्ट यूपी में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट जनता के बीच में चल रहे हैं वह सब उनकी देन हैं।

1974 में बच्चों ने किया था अभिवादन : बसंल

पूर्व विधायक व कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विवेक बंसल ने बताया कि यह बात है 1974 की जब हम अवर लेडी फातिमा में पढ़ते थे। तब वह अलीगढ़ आईं थी। वह दोदपुर क्षेत्र में होते हुए खुली कार में बैठकर गुजरी थीं। तब स्कूली बच्चों में हम भी शामिल थे। तब सड़क के किनारे लाइन लगवाकर खड़ा किया गया था। कागज की झंडियां फहराईं गई थीं और इंदिरा जी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया था। आयरन लेडी के समय में भारत प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी रहा है। देश को तमाम ख्याति उन्होंने ही दिलवाई हैं।

अलीगढ़ से लगाव :

* कासिमपुर पावर हाउस और साथा चीन मिल का किया था उद्घाटन।
* 1977 में कांग्रेस नेता अशोक चौहान के समर्थन में की थी रैली।
* 1978 में कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता अहमद खां की बेटी के शादी समारोह में भी हुईं थीं शरीक।

संपादकीय

केंद्रीय एजेंसिया

राष्ट्र-राज्य के लिए इसे एक अभूतपूर्व संकट मानना होगा। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का अपने राज्यों में प्रवेश निषेध करना ऐसा कदम है, जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। चन्द्रबाबू नायडू सरकार ने तो सीबीआई के साथ सभी केंद्रीय एजेंसियों के स्वत: प्रवेश के रास्ते बंद कर दिए हैं। साथ ही कई केंद्रीय कानूनों और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अपने राज्य में क्रियान्वयन को दी गई सहमति भी वापस ले लिया है। दोनों ने इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरु पयोग का तर्क दिया है। केंद्र सरकार इससे नाखुश है और वित्त मंत्री अरु ण जेटली के वक्तव्य इसे प्रमाणित करते हैं। केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक दुरु पयोग हमारे यहां लंबे समय से मुद्दा रहा है। इस समय सीबीआई वैसे भी कठघरे में खड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी नियति तय करने वाला है। किंतु इसके आधार पर आप एजेंसियों को ही नकार दें इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। सत्ता का राजनीतिक टकराव इस सीमा तक नहीं जाए कि देश में केंद्र राज्य संबंधों के तंतु ही टूटने लगे। इन राज्य सरकारों ने राजकीय सीआईडी से मामले की जांच कराने का निर्णय किया है। क्या प्रदेश की राजनीतिक सत्ता सीआईडी का दुरूपयोग नहीं करती ? अनेक अपराधों का दायरा कई राज्यों तक फैला होता है। उसकी जांच और कानूनी कार्रवाई कैसे होगी ? जिस अपराध का विस्तार देश की सीमा से बाहर हो और अपराधी भी विदेश में हों उनका क्या होगा ? इन दो राज्यों के निर्णयों से ऐसे अनेक प्रश्न खड़े हो गए हैं जिनका उत्तर मिल ही नहीं सकता। संविधान में कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इसीलिए केंद्र के पास पुलिस नहीं है। बावजूद केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई तो उसके ठोस कारण हैं। अपराध के तौर-तरीके और आयाम जितने विस्तृत और खतरनाक हो गए हैं, उनमें अनेक मामलों की छानबीन एवं कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना राज्यों की पुलिस के वश में नहीं होता। राज्यों की पुलिस जांच पर भी प्रश्न उठते हैं और लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो क्या उन मांग करने वालों का मुंह आप बंद कर देंगे ? वास्तव में एजेंसियों के दुरूपयोग रोकने के उपाय अवश्य किए जाएं पर उसकी आड़ में इस तरह की गैरजिम्मेवार एवं खतरनाक राजनीति का पुरजोर विरोध करना चाहिए। केंद्र इसके खिलाफतुरंत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए।

गुटों की हताशा, परेशानी घबराहट

पिछले 36 घंटे में दो युवकों की बर्बर हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। इस वारदरत से हर कोई सन्न है। जिस तरह से मुखबिरी के शक में दोनों अपहृत युवकों को गला रेतकर और सिर में कई गोलियां मार कर मौत के घाट उतारा है, वह राज्य में सक्रिय आतंकी गुटों की हताशा, परेशानी और घबराहट को बयां करती है। गौरतलब है कि पिछले 48 घंटे में कुल छह युवकों को अगवा कर लिया गया, जिसमें से दो युवकों की जहां हत्या कर दी गई वहीं तीन को छोड़ देने की भी खबर है। और बाकी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। घाटी में ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता होगा जब आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ नहीं होती हो या एकाध आतंकवादी नहीं मारे जाते हों। लेकिन आतंकी वारदात खत्म होने या कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जबकि सेना 2017 से ''ऑपरेशन ऑलआउट' कर रही है। उसे सफलता भी मिली है। इस साल अब तक विभिन्न गुटों के 200 से ज्यादा आतंकवादी सुरक्षाबलों के हाथों मारे गए हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, हिज्बुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद गुट शामिल हैं। ऑपरेशन आलआउट ने वाकई घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की कमर तोड़ी है, मगर बीच-बीच में जिस तरह से आतंकवादी कभी सुरक्षाकर्मियों को तो कभी पुलिसवालों को और कभी आम नागरिकों पर हमलावर हैं, उससे इस बात पर भी संजीदगी से मंथन की जरूरत है कि हमसे चूक कहां हो रही है? आखिर तमाम प्रयासों-वार्ताकार की नियुक्ति से लेकर सेना का बेहद सख्त रुख अपनाने-के बावजूद घाटी में अमन का माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है? सूबे में शांति लाने का दावा करने वाले कहां गए? किसकी नीति फेल हुई-दिल्ली की या राज्य में तैनात जिम्मेदार लोगों की? वैसे आतंकवादियों द्वारा इससे पहले भी अगस्त माह में पुलिसवालों के रिश्तेदारों को अगवा करने की घटना हुई थी, मगर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। किंतु इस बात स्थानीय युवकों को निशाना बनाने की वजह सुरक्षाबलों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। खुफिया तंत्र की विफलता भी इस ओर इशारा करती है। क्योंकि पिछले महीने आतंकी गुटों ने स्थानीय लोगों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। क्या इसे समझने में हम चूक गए?

सत्संग

सर्वसाधारण

मृत, पारस और कल्पवृक्ष यह तीनों महान् तत्त्व सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। हम जितना उनसे दूर रहते हैं उतने ही ये हमारे लिए दुर्लभ हैं परन्तु जब हम इनकी ओर कदम बढ़ाते हैं तो यह अपने बिल्कुल पास, आ जाते हैं। जिस ओर मुंह न हो उधर की चीजों का कोई अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता। पीठ पीछे क्या वस्तु रखी हुई है, इसका पता नहीं चलता, किन्तु उलट कर जैसे ही हम मुंह फेरते हैं वैसे ही पीछे की चीज दिखाई देने लगती है। यह स्पष्ट है कि जिधर हमारी प्रवृत्ति होती है, जैसी हम इच्छा और आकांक्षाएं करते हैं उसी के अनुरूप, वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। कहने को तो सभी कोई सुखदायक स्थिति में रहना और दु:खदायक स्थिति से बचना चाहते हैं, परन्तु यह हीन वीर्य चाहना, शेखचिल्ली के मंसूबों की तरह निष्फल और निर्थक सिद्ध होती है। सच्ची चाहना की कसौटी यह है कि अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने की लगन अन्त:करण की गहराई तक समाई हुई हो। आकांक्षा की तीव्रता का स्पष्ट सबूत अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने के प्रयत्न में भी जान से जुट जाना है। धुन का पक्का, निश्चित मार्ग का दृढ़ प्रतिज्ञ पथिक अपनी अविचल साधना के द्वारा ऊंचे से ऊंचे सुदूर लक्ष्य तक आसानी से पहुँच जाता है। इस विश्व में कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि मनुष्य सच्चे मन से इच्छा करने पर भी उसे प्राप्त न कर सके। लोभवश अनावश्यक वस्तुओं के संचय की लालसा में प्रकृति के नियम कुछ बाधक भले ही बनें, परन्तु आत्मिक सद्गुणों के विकास द्वारा सात्विक आनन्द प्राप्त करने की आकांक्षा तो सर्वथा उचित और आवश्यक होने के कारण पूर्णतया सरल है, उसकी पूर्ति में ईरीय सहायता प्राप्त होती है। आत्म-कल्याण करने वाले सत् प्रयासों में भगवान् सदा ही अपना सहयोग देते हैं। अमृत, पारस और कल्पवृक्ष मनुष्य के लिए पूर्णतया सुलभ हैं बशत्रे कि उन्हें प्राप्त करने का सच्चे मन से प्रयत्न किया जाए। अपने अविनाशी होने का दृढ़ विास चिन्तन और मनन द्वारा अपनी अंत: चेतना में भली प्रकार बिठाया जा सकता है। यह विास इतना मजबूत होना चाहिए कि जीवन के किसी भी प्रश्न पर विचार किया जाए तो उस समय यह विास स्पष्ट रूप से बीच में आ उपस्थित हो कि-यह जीवन, हमारे महा जीवन, अनंत जीवन का अंश मात्र है। महा जीवन के लाभ-हानि को प्रधानता देने की नीति के आधार पर जीवन की गुत्थियों को सुलझाना चाहिए, उसी अनुसार कार्यक्रम नाना चाहिए।

स्थानापन्न कराने की नीति पर विराम

पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मित्र समझे जाने वाले मोहम्मद नाशीद समेत कई नेताओं से गले मिलने की तस्वीरें भी सुखद थीं। वस्तुत: गर्मजोशी के ये हाव-भाव बता रहे थे कि पूर्व शासन द्वारा अकारण उदण्डतापूर्वक भारत को मालदीव से बाहर करने और चीन द्वारा स्थानापन्न कराने की नीति पर विराम लगने की शुरु आत हो गई है। राष्ट्रपति सोलिह और नाशीद दोनों और उनकी मालदीवियन डेमोक्रटिक पार्टी भारत की ईमानदार मित्रता और इसके नि:स्वार्थ सहयोगी व्यवहार के समर्थक हैं। शपथ ग्रहण के बाद मोदी और सोलिह दोनों ने एक-दूसरे की चिंताओं और भावनाओं का सम्मान करने और हिन्द महासागर के इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने पर जो सहमति व्यक्त की उसके मायने व्यापक हैं। राष्ट्रपति सोलिह ने संबंधों में भारत को प्राथमिकता देने का संकेत देकर तस्वीर साफ कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की मूर्खता से मालदीव चीन के कर्ज में बुरी तरह फंसा हुआ है।

सतीश पेडणोकर

राजधानी माले में यह दृश्य देखने के लिए भारतीय तरस रहे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में सर्वोच्च रैंकिंग वाले राजकीय अतिथि थे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मोदी मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और मौमून अब्दुल गयूम के बीच में बैठे थे। यह दृश्य हर उस व्यक्ति को भावुक कर रहा था, जो मालदीव के साथ भारत के पारंपरिक रिश्तों से वाकिफ हैं। इसमें चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्री लू शुगांग भी शामिल हुए लेकिन वो एक सामान्य अतिथि की तरह थे। माले हवाई अड्डे पर मोदी का जैसा शानदार स्वागत हुआ वह यह बता रहा था कि स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं।

पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मित्र समझे जाने वाले मोहम्मद नाशीद समेत कई नेताओं से गले मिलने की तस्वीरें भी सुखद थीं। वस्तुत: गर्मजोशी के ये हाव-भाव बता रहे थे कि पूर्व शासन द्वारा अकारण उदण्डतापूर्वक भारत को मालदीव से बाहर करने और चीन द्वारा स्थानापन्न कराने की नीति पर विराम लगने की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति सोलिह और नाशीद दोनों और उनकी मालदीवियन डेमोक्रटिक पार्टी भारत की ईमानदार मित्रता और इसके नि:स्वार्थ सहयोगी व्यवहार के समर्थक हैं। शपथ ग्रहण के बाद मोदी और सोलिह दोनों ने एक-दूसरे की चिंताओं और भावनाओं का सम्मान करने और हिन्द महासागर के इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने पर जो सहमति व्यक्त की उसके मायने व्यापक हैं। राष्ट्रपति सोलिह ने संबंधों में भारत को प्राथमिकता देने का संकेत देकर तस्वीर साफ कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की मूर्खता से मालदीव चीन के कर्ज में बुरी तरह फंसा हुआ है। उन्होंने चीन के काम करने की खुली छूट दे दी। मोटा-मोटी आकलन यह है कि चीन का करीब 1.5 अरब डॉलर का कर्ज मालदीव पर होगा।

सोलिह ने कहा कि यह पूरा हिसाब नहीं है, कर्ज ज्यादा हो सकता है। 4 लाख की आबादी वाले देश के लिए यह कितना बड़ा कर्ज है, इसे समझना कठिन नहीं है। सोलिह सरकार ने चीन के कर्जे और उसके रिस्ट्रक्चरिंग पर काम आरंभ कर दिया है। इसमें भारत सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है। भारत के हित में यही है कि कठिनाई के बावजूद तुरंत मालदीव को इतनी वित्तीय मदद दे, जिससे वह चीनी कर्ज दबाव से मुक्त हो सके। वस्तुत: रणनीतिक रूप से इस महत्त्वपूर्ण देश से भारत को यामीन ने व्यवहार में निष्क्रिय और अंशत: बाहर कर दिया था। यामीन ने भारत की परियोजनाओं को रोक देने की स्थिति पैदा की, चीन को ठेके पर ठेके दिए, यहां तक कि बिजली पैदा करने का ठेका पाकिस्तान को दिया गया। चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता और भारतीयों के लिए वर्क वीजा पर भी अघोषित प्रतिबंध लग गया था। मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स जैसे देशों को हेलिकॉप्टर, पेट्रोल बोट और सैटेलाइट सहयोग देना हिन्द महासागर में भारत की नौसेना रणनीति का हिस्सा रहा है। यामीन अपने क्षेत्र में इसे खत्म करने का उदण्ड प्रयास कर रहे थे। हिन्द महासागरीय क्षेत्र का सबसे निकट का देश होने के कारण भारत की सामुद्रिक क्षेत्र सुरक्षा को देखते हुए इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। यामीन ने कई द्वीप चीन को सौंपे। उनके जहाज वहां बेरोकटोक आने-जाने लगे। चीनी पोत और पनडुब्बियों ने वहां लंगर भी डाल रखा है। उनके फैसलों से हमारे यहां उत्तेजना पैदा हुई थी। सरकार पर वहां कुछ करने का दबाव था। मालदीव की विपक्षी पार्टियां भी भारत से हस्तक्षेप कर शासन को उखाड़ फेंकने का अनुरोध कर रहीं थीं। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम और मोहम्मद नशीद ने अपने निर्वासन स्थल से ही कई बार भारत से सैनिक हस्तक्षेप की गुहार लगाई। बावजूद भारत ने सैनिक हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं समझा। नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति में नेबर फर्स्टयानी पड़ोसी पहला प्रमुख स्तंभ है। इसके तहत उन्होंने सभी पड़ोसी देशों की यात्रा कीं। चाहते हुए भी मालदीव नहीं जा सके। 2015 में निर्धारित यात्रा प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण रद्द करनी पड़ी थी। भारत ने धैर्य के साथ मालदीव के लिए रणनीति बनाकर काम करना आरंभ किया। यह संदेश दिया गया कि भारत अपने समर्थकों के साथ है। यामीन ने संसद से 9 विपक्षी सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विपरीत फैसला दिया तो पुलिस ने न्यायालय को ही घेर लिया। देश में 5 फरवरी को आपातकाल लागू कर इन्हें भी जेल के अंदर बंद कर दिया। भारत ने आपातकाल और विरोधियों को दमन करने की नीति की न केवल आलोचना की बल्कि साफ मांग की कि मोहम्मद नशीद को वापस बुलाए, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करे और चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बहाल करे। भारत ने सीधा हस्तक्षेप फिर भी नहीं किया। वस्तुत: भारत ने शांति से नेपय में रहते हुए उनकी विदाई के लिए हरसंभव कोशिशें कीं। विश्व स्तर पर प्रचार किया कि मालदीव के वर्तमान शासन के तहत निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। भारत की सक्रियता से अमेरिका और ब्रिटेन ने बयान जारी कर दिया कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो मालदीव पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इससे मालदीव के विपक्षी नेताओं का मनोबल बढ़ा और जनता के बीच भी संदेश गया। यामीन दबाव में आ गए। भारत ने विपक्षी दलों के बीच एकता कायम कराई, जिनने गठबंधन करके संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर सोलिह को उतारा। किंतु 24 सितम्बर को चुनाव परिणाम आ जाने के बावजूद यामीन सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने इस बार अपनी ताकत उनको दिखाई। भारत ने उनको अच्छी भाषा में समझा दिया कि आप जनादेश का सम्मन करिए नहीं तो हमें कुछ करना होगा। चीन भी जनादेश नकारकर सत्ता में बैठे रहने के लिए सरेआम मदद नहीं कर सकता था। डेढ़ महीने की रस्साकशी में राजनीतिक स्थिति को यहां तक लाने में मुख्य भूमिका भारत की ही रही है। अब प्रधानमंत्री के वहां जाने से ही यह संदेश चला जाएगा कि नई सरकार के साथ भारत खड़ा है। मोहम्मद नशीद के स्वदेश लौटने के बाद उनका प्रभाव सरकार पर रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति गयूम भी भारत के साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी बता रही है कि सामरिक संबंधों पर भी निर्णय हुए हैं। यामीन की भारत विरोधी नीतियों के कारण कई चीजें नये सिरे से आरंभ करने की जरूरत है तो कई को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की। तो हम मालदीव भारत संबंधों में फिर नये सिरे से एक बेहतर दौर की संभावना देख सकते हैं।

चलते चलते

''भ्रष्टाचार के खात्मे'

ज्यादा असरदार दिखाने के लिए नेता नित नये प्रयोग भी कर रहे हैं। कहीं कोई गंगाजल की सौगंध खा रहा है तो कहीं कोई धर्मग्रंथों की दुहाई दे रहा है। यह सतरंगी छटा छत्तीसगढ़ में दिख रही है। यहां वादा करने

राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। नेता वादों की झड़ी लगा रहे हैं। अपने वादों को ज्यादा असरदार दिखाने के लिए नेता नित नये प्रयोग भी कर रहे हैं। कहीं कोई गंगाजल की सौगंध खा रहा है तो कहीं कोई धर्मग्रंथों की दुहाई दे रहा है। यह सतरंगी छटा छत्तीसगढ़ में दिख रही है। यहां वादा करने और वादे पर अडिग रहने की ''कलाकारी' सूबे के नेता बखूबी प्रदर्शित कर रहे हैं। एक तरफजहां कांग्रेस के नेता पत्रकार वार्ता में हाथों में गंगाजल लेकर सत्तासीन होने के 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्जमाफी का भरोसा जता रहे हैं, वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी चुनाव बाद भाजपा से गठबंधन ना करने का वादा आठ धार्मिक ग्रंथों की कसम खाकर कर रहे हैं। सवाल यह कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि नेताओं को अपने कहे पर भरोसा नहीं रहा। इसके लिए उन्हें धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल, उल्लखित दोनों उदाहरण नेताओं द्वारा जनता की नजरों में राजनीतिक बिरादरी की लगभग शून्य हो चुकी विश्वसनीयता को जिंदा रखने की कोशिश भर है। ''गरीबी हटाओ' से ''भ्रष्टाचार के खात्मे' तक के वादे समय के साथ गायब होते जा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि अधिकतर चुनाव आम लोगों के रोजमर्रा की समस्याओं की जगह भावनात्मक लफ्फेबाजी पर लड़े जाते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि नेता भी जनता के मनोभाव को जानते हैं तो जनता भी नेताओं के भरोसे की बखूबी समझ रखती है। नेता और उसके वादे का एक किस्सा 1980 के रायबरेली चुनाव का है। समाजवादी राजनारायण 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हराने के बाद दोबारा जनता के बीच थे। एक सभा में लोगों ने जब उन्हें उनके अधूरे चुनावी वादों के बारे में याद दिलाया तो उन्होंने टका सा जवाब दिया-जब देश की प्रधानमंत्री के रहते जो काम नहीं हुआ, उसकी उम्मीद मुझसे बेमानी होगी। अगर वादा और वादाखिलाफी के व्यावहारिक शास्त्र के नजरिये से देखें तो इसमें बड़ी खामी नेताओं के अपने वादों के प्रारूप (मॉडल) पर काम किए बगैर घोषणा करने का है, जो पूरा न होने की सूरत में आलोचना की वजह बनती है। बेहतर होगा नेता अपनी घोषणाओं के साथ उसे लागू करने का प्रारूप भी लोगों के सामने रखें। तभी लोकतंत्र को खाद-पानी मिलता रहेगा।

फोटोग्राफी...

मलयालम माह ''वृश्चिकम' के दूसरे दिन रविवार को सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शनों के लिए लाइन में खड़े श्रद्धालु।

सुरक्षा की गारंटी

रक्षा कवच को मजबूत करते हुए स्वदेशी तकनीक से बनी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। अपना पहला गश्ती अभियान पूरा करने के बाद देश की पहली परमाणु पनडुब्बी आइएनएस अरिहंत को देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह पनडुब्बी 125 करोड़ भारतवासियों की सुरक्षा की गारंटी है। अरिहंत शांति के दुश्मनों के लिए कड़ा संदेश और परमाणु ब्लैकमेलिंग का जवाब है। असल में आईएनएस अरिहंत भारत में ही बनाई और डिजाइन की गई देश की पहली परमाणु पनडुब्बी है। जमीन और आकाश के बाद अब पानी के भीतर से परमाणु वार करने की भारत की क्षमता को पूरा करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। असल में पानी के अंदर परमाणु हमला करने की क्षमता किसी भी परमाणु देश के सामरिक हितों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि परमाणु हमला होने की स्थिति में पलटवार करने के लिए पानी के भीतर के हथियार सुरक्षित रहते हैं। अरिहंत का मतलब होता है दुश्मन को नष्ट करने वाला। यह जल, थल और नभ में मार करने में सक्षम है। इसे न्यूक्लियर ट्रायड भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तीनों स्तर की सुरक्षा। आईएनएस अरिहंत की इस सफलता से भारत वायु, जल और थल तीनों से परमाणु हमला करने वाला देश बन गया है। आईएनएस अरिहंत ने पहले परमाणु हमला ना करने के भारत की नीति को असली धार दी है, क्योंकि माना जाता है कि दुश्मन अपने पहले परमाणु हमले में ही पलटवार करने की ताकत को खत्म करने की कोशिश करता है। दरअसल, डीजल और इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को कुछ दिन में पानी के भीतर से ऊपर आना ही पड़ता है। परमाणु पनडुब्बी के साथ ऐसी मजबूरी नहीं है। परमाणु रिएक्टर से चलने वाली परमाणु पनडुब्बी महीनों गहरे पानी में डूबी रहती है। इसलिए दुश्मन उसका पता नहीं लगा पाता। परमाणु बम वाली कुल 16 मिसाइलों से लैस आईएनएस अरिहंत दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसमें 750 किलोमीटर तक मार करने वाली यू-15 सागरिका और 3,500 किलोमीटर तक मार करने वाली य-4 मिसाइलें हैं। दोनों को पानी के भीतर से छोड़ा जा सकता है। हालांकि इस ताकत को जुटाने में भारत को कई चुनौतियों से पार पाना पड़ा क्योंकि कोई भी देश परमाणु पनडुब्बी की तकनीक देने के लिए राजी नहीं था। दुनिया के गिने चुने देश ही अभी तक परमाणु पनडुब्बी बना सके हैं। इनमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल हैं। भारत की स्थिति पड़ोसी देश चीन मुकाबले बहुत अच्छी नहीं है। चीन के पास इस समय लगभग 5 परमाणु पनडुब्बियों समेत करीब 50 से 60 पनडुब्बियां हैं, जबकि भारत के पास लगभग 15 पनडुब्बियां हैं।

जल में मारक इस रेस में अमेरिका 70 से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि 30 परमाणु पनडुब्बियों के साथ रूस दूसरे नंबर पर है। यूके के पास 12 और फ्रांस के पास 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं। जहां चीन, अमेरिका और रूस की पनडुब्बियां 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली हैं, वहीं आईएनएस अरिहंत की क्षमता 750 से 3500 किलोमीटर तक की है। निस्संदेह स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आइएनएस अरिहंत के नौसेना में शामिल होने से देश की सामरिक ताकत बढ़ेगी। लेकिन देश की रक्षा जरूरतों पर विदेशी निर्भरता खत्म करने के लिए हमें खुद की औद्योगिक सैन्य संस्कृति विकसित करनी होगी। तभी विकसित राष्ट्र बनने का हमारा सपना साकार हो सकता है।

सार समाचार

संसद को भंग करके जल्द चुनाव कराना 'गैर जिम्मेदाराना'- नेतन्याहू

येरूशलम। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि संसद को भंग करके जल्द चुनाव कराना 'गैर जिम्मेदाराना' कदम होगा। नेतन्याहू ने यह संदेश सोमवार को जारी किया। इससे कुछ ही क्षण पहले, उनके शिक्षा मंत्री नाफ़ताली बेनेट को यह ऐलान करना था कि उनकी जूइश होम पार्टी गठबंधन से अलग हो रही है या नहीं। अगर बेनेट गठबंधन से चले जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी और नए चुनाव कराने होंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते हमास के साथ संघर्ष विराम किया था, जिसका विरोध करते हुए बेनेट ने गठबंधन से नाता तोड़ने की धमकी दी है। इस संघर्ष विराम के विरोध में रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने इस्तीफा दे दिया था। बेनेट ने गठबंधन में रहने के लिए रक्षा मंत्रालय देने की शर्त रखी है, लेकिन रविवार रात नेतन्याहू ने कहा कि वह यह मंत्रालय अपने पास रखेंगे।

डब्ल्यूटीओ के एजेंडे में पुराने, नये सभी मुद्दे शामिल होने चाहिये : प्रभु

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने सोमवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की प्रासंगिकता को बनाये रखने के लिये उसके एजेंडे में पुराने और नये दोनों मुद्दे शामिल किये जाने चाहिये। प्रभु ने कहा कि डब्ल्यूटीओ के सामने कई चुनौतियां हैं और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। विधि फर्म लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन तथा उद्योग चैंबर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हमें इस बात पर सहमत होना चाहिये कि डब्ल्यूटीओ के बिना हमें व्यापार में दिक्कत होगी क्योंकि हमें वैश्विक व्यापार की जरुरत है ... इसलिये हमें यह सुनिश्चित करने की जरुरत है कि डब्ल्यूटीओ बरकरार रहे। डब्ल्यूटीओ में बेहतरी के लिये बदलाव होना चाहिये।'

प्रभु ने कहा कि सभी सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर एजेंडा तैयार किया जा रहा है। यह सभी सदस्य देशों को मुंजर होगा और सभी महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें शामिल किये जायेंगे। उन्होंने कहा, 'हम उन मुद्दों को नहीं भूल सकते हैं जिन्हें सभी सदस्य देशों की सहमति से चर्चा के लिये टेबल पर रखा गया ... इसलिये हमें इन मुद्दों का ध्यान रखना होगा। इस समय हम नये मुद्दों को शामिल करना भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिये हमें एक व्यवस्थित एजेंडा पेश करना होगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण मुद्दों का समावेश हो।'भारत समेत विकासशील देश कृषि सब्सिडी से जुड़े मुद्दों का हल चाहते हैं जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश ई-कॉमर्स एवं निवेश से जुड़े नये मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं।

कट्टर मुस्लिमों पर सख्त हुआ चीन, 30 दिन में सरेंडर करने का दिया आदेश

बीजिंग (एजेंसी)।

चीन के प्रशासन ने अपने प्रांत शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ तेवर सख्त कर दिए हैं. चीन सरकार ने उन कट्टर लोगों से 30 दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा है, जो आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं. यहां पर लंबे समय से चीन उइगर मुस्लिमों से उनकी धार्मिक गतिविधि रोकने के लिए दबाव बना रहा है. पिछले दिनों यहां तक खबर आई थी कि चीन ने बाकायदा यहां से लाखों युवकों को एक कैंप में रखा हुआ है. इन्हें यहां पर चीन के साम्यवाद के बहाने उनके धर्म से अलग करने की योजना बनाई जा रही है.

चीन ने अब यहां पर ऐसे ग्रुप को निशाना बनाना शुरू किया है, जो विदेशी मदद से शिनजियांग में कट्टरता और आतंकवाद को

बढ़ावा देना चाहते हैं. चीन ने अब ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया है कि वह 30 दिन के अंदर पुलिस के सामने सरेंडर कर दें. अगर उन्होंने सरेंडर कर अपने जुर्म को कबूल कर लिया तो उनके खिलाफ प्रशासन कम सख्ती दिखाएगा और कोशिश करेगा कि उन्हें कम से कम सजा हो. इस बारे में हामी शहर के प्रशासन ने अपने आफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक संदेश पोस्ट किया है.

चीन पर उइगर मुस्लिमों के खिलाफ सख्ती के आरोप के बाद पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है. कई विदेश एजेंसियों की निगाहें भी बीजिंग के ऊपर जमीं हुई हैं. लेकिन खुद चीन इन आरोपों को नकार चुका है.

सरकारी आदेश के मुताबिक, 'ऐसे सभी लोगों को सरेंडर करने का आदेश दिया जाता है, जो आतंकवाद से जुड़े अपराधों में शामिल रहे हैं या फिर अतिवाद, अलगाववाद और आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं. ऐसे लोगों को आदेश है कि 30 दिन के भीतर सरेंडर करें, अपने अपराध को स्वीकार करें और उसके तथ्य मुहैया कराएं.'

खालिदा जिया ने भ्रष्टाचार के मामले में अदालत में अपनी सजा को दी चुनौती

ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें सुनायी गयी सात साल की सजा को रविवार को अदालत में चुनौती दी और दावा किया कि उन्हें 'अवैध और अनुचित तरीके से' दोषी ठहराया गया है। उन्हें उनके दिवंगत पति के नाम पर स्थापित एक चैरिटेबल ट्रस्ट से लाखों टका की हेराफेरी के आरोप में सजा सुनायी गयी है। सुनवाई अदालत ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रमुख को 29 अक्टूबर को सजा सुनायी थी। पूरे फैसले की प्रति मिलने के चार दिन बाद जिया ने इसे चुनौती दी। बीडीएन्यूज के अनुसार उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद उनके वकील कैसर कमल ने कहा कि 700 पृष्ठों की अपील याचिका में जमानत याचिका भी शामिल है। वकील ने कहा, 'हमने उसकी सजा को खारिज करने और उनकी रिहाई के लिए अपील की है। अपील पर फैसला करने के लिए उच्च न्यायालय की एक पीठ का गठन किया जाएगा।' जिया (73) आठ फरवरी से एक अन्य मामले के सिलसिले में हिरासत में हैं।

जिस किम जोंग उन की सनक से थर्राती है दुनिया, उसी देश का युवा उससे नहीं खाता खौफ

तोक्यो (एजेंसी)।

पिछले वर्ष गोलीबारी के बीच भागकर दक्षिण कोरिया जाने वाला उत्तर कोरिया का सैनिक एक मेजर जनरल का बेटा है. लेकिन उसका कहना है कि उसकी आयु के ज्यादातर उत्तर कोरियाई लोगों की किम जोंग उन के प्रति कोई निष्ठा नहीं है. जापान के एक अखबार में यह बताया गया है. पिछले वर्ष ओ चांग सांग असैन्यीकृत क्षेत्र में पानमुनजोम गांव के रास्ते सीमा पार कर गया था. उस पर उसके ही साथियों ने गोलियां चलाईं जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. वह बुरी तरह जख्मी हुआ था. यह खबर सुर्खियां बनी थीं. जापान के सानकेई शिमबन अखबार के मुताबिक, ओ (25) एक मेजर जनरल का बेटा है.

अखबार ने उसका पहला मीडिया साक्षात्कार छापा है. इसमें उसने कहा है कि उत्तर कोरिया में लोग, खासकर युवा पीढ़ी एक दूसरे के प्रति, राजनीति के प्रति और अपने नेताओं

के प्रति उदासीन हैं. उनमें निष्ठा की कोई भावना नहीं है. '' ओ ने कहा, '' मेरी पीढ़ी के संभवत- 80 फीसदी लोग उदासीन हैं और किसी के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है''.

क्यूबा के राष्ट्रपति ने प्योंगयांग में किम जोंग की मुलाकात, अंतरराष्ट्रीय हालातों पर हुई चर्चा

उत्तर कोरिया के दौरे पर आए क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-केनल ने प्योंगयांग में देश के नेता किम जोंग उन से मुलाकात की और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात के 'साझा चिंता के महत्वपूर्ण विषयों' पर चर्चा की. क्यूबा के राष्ट्रपति का प्योंगयांग दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, वाशिंगटन ने कुछ ही दिन पहले क्यूबा पर ताजा आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं. लगभग आधी सदी तक चले वैमनस्य के बाद अमेरिका के क्यूबा के साथ संबंध 2015 में बहाल हुए थे. लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर तल्खी आई है.

वामपंथी शासन वाला क्यूबा उत्तर कोरिया के कुछ बचे हुए सहयोगियों में से एक है. आधिकारिक समाचार एजेंसी केसीएनए ने बताया, साझा चिंता के अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हुआ है. यह बातचीत अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर हुई और सभी मुद्दों पर आम राय बन गई है.

अफगानिस्तान में चीन के साथ और अधिक संयुक्त परियोजनाओं का पक्षधर है भारत

बीजिंग। (एजेंसी)।

भारत ने सोमवार को कहा कि वह अफगानिस्तान में चीन के साथ और अधिक संयुक्त परियोजनाएं संचालित करना चाहेगा जबकि दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षित 10 अफगान राजनयिकों के पहले जत्थे ने नयी दिल्ली में प्रशिक्षण के बाद यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। नयी दिल्ली में 15 से 26 अक्टूबर तक प्रशिक्षण पाने वाले अफगान राजनयिकों ने सोमवार को चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया। अफगानिस्तान में भारत और चीन द्वारा संचालित किया जा रहा यह पहला संयुक्त कार्यक्रम है। इसके लिए इस साल अप्रैल में चीन के वुहान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अनौपचारिक शिखरवार्ता में सहमति बनी थी। चीन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बीजिंग में भारत के उप राजदूत एक्रिनो विमल ने कहा, ''हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में हम और अधिक परियोजनाएं चिह्नित करेंगे जिन्हें भारत और चीन की सरकारें अफगानिस्तान के भले के लिए संचालित कर सकती हैं, जिसकी इच्छा अफगानिस्तान की सरकार और जनता ने व्यक्त की है।''

इंडोनेशिया : खुफिया एजेंसी का दावा, मस्जिदों में नमाजियों को पढ़ाया जाता है कट्टरता का पाठ

जकार्ता (एजेंसी)।

इंडोनेशिया की खुफिया एजेंसी ने सोमवार को खुलासा किया कि इंडोनेशिया की दर्जनों मस्जिदें जिनमें सरकारी कर्मचारी जाते हैं, वो कट्टरता फैला रही हैं और गैर-मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के लिए कहती हैं. एजेंसी की इस रिपोर्ट से छह महीने पहले ही देश के दूसरे सबसे बड़े शहर सुरबाया में कई चर्चों में रविवार की प्रार्थना के दौरान आत्मघाती बम हमले हुए थे जिनमें एक दर्जन लोग मारे गये थे. वो करीब एक दशक में हुए सबसे भयावह आतंकी हमले थे और दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश में

उस घटना ने धार्मिक असहिष्णुता को उजागर किया था.

इंडोनेशिया स्टेट इंटेलीजेंस एजेंसी ने सोमवार को कहा कि उसने जुलाई से इस दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह की करीब एक हजार मस्जिदों में पड़ताल की और पता चला कि जकार्ता के पास करीब 41 मस्जिदों के इमाम नमाजियों को कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे थे और इन लोगों में अधिकतर सरकारी सेवक थे जो पास के सरकारी मंत्रालयों में काम करते हैं.

एजेंसी ने पाया कि करीब 17 मौलानाओं ने इस्लामिक स्टेट के लिए समर्थन या सहानुभूति जताई और लोगों को सीरिया तथा मरावी में जिहादी समूह के लिए संघर्ष को उकसाया. एजेंसी के प्रवक्ता वावन पुरवंतो ने एएफपी से कहा, ''इन मस्जिदों में जाने वाले अधिकतर लोग सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए यह बात चिंताजनक है.

सिंगापुर में भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 14 प्रतिशत वृद्धि

मुंबई (एजेंसी)।

सिंगापुर को भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या 2018 में 14 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। उसकी कोशिश युवा पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने की है। सिंगापुर पर्यटन बोर्ड के दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक जी. बी. श्रीधर ने यहां पीटीआई से कहा, ''पिछले साल (2017 में) 12.7 लाख भारतीय पर्यटकों ने सिंगापुर की यात्रा की। इस साल जनवरी से सितंबर तक में ही 10.8 लाख भारतीय पर्यटक सिंगापुर की यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में हमें पर्यटकों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले इस साल 14 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।''उन्होंने कहा कि 2017 में रिकॉर्ड संख्या में भारतीय पर्यटकों ने सिंगापुर की यात्रा की। ऐसे में सिंगापुर आने वाले पर्यटकों की संख्या के लिहाज से भारत तीसरे स्थान पर है। जबकि चीन पहले और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- दर्दनाक खशोगी की टेप नहीं सुनना चाहता

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें पत्रकार खशोगी की हत्या की ऑडियो रिकार्डिंग के बारे में पूरी तरह बता दिया गया है लेकिन वह स्वयं उसे सुनना नहीं चाहते। उन्होंने 'फोक्स न्यूज संडे' के साथ साक्षात्कार में कहा, ''क्योंकि यह बहुत ही दर्दनाक टेप है। यह भयावह टेप है।''यह साक्षात्कार शुक्रवार को हुआ। ट्रंप ने कहा, ''यह बहुत ही हिंसक, बहुत ही दुष्टतापूर्ण और भयावह था।''अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्हें पत्रकार खशोगी की जघन्य हत्या से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में सबकुछ बता दिया गया है, लेकिन उन्हें इन ''दर्दनाक'' टेपों को नहीं सुनने की सलाह दी गयी है। खशोगी (59) 'वाशिंगटन पोस्ट' के लिये लिखा करते थे। पिछले महीने तुर्की में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर उनकी हत्या कर दी गयी थी। वह अपनी शादी से संबंधित दस्तावेज लेने के लिये दूतावास गये थे।

तुर्की के जांचकर्ताओं ने बताया कि उनके पास खशोगी की हत्या की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसे उन्होंने अमेरिका समेत अपने अहम सहयोगी देशों के साथ साझा किया है। ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज' के क्रिस वैलेस के साथ साक्षात्कार में पहली बार यह माना कि उन्हें खशोगी की हत्या की ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में सबकुछ बताया गया है। यह साक्षात्कार रविवार को प्रसारित हुआ। समाचार चैनल के अनुसार ट्रंप ने कहा कि उन्होंने टेप नहीं सुना है क्योंकि उन्हें इस ''दर्दनाक'' टेप को नहीं सुनने की सलाह दी गयी थी। एक दिन पहले ही ट्रंप ने खशोगी की हत्या को लेकर जांच एजेंसी का आकलन जानने के लिये सीआईए प्रमुख के साथ बात की थी। मंगलवार तक उन्हें इस पर विस्तृत रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। एक दिन पहले ट्रंप ने कैलिफोर्निया में संवाददाताओं से कहा था, ''यह (खशोगी की हत्या) बेहद भयावह घटना थी।''

परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए ईरान जाएंगे ब्रिटिश विदेश मंत्री जेरेमी हंट

माले (एजेंसी)।

लंदन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट परमाणु करार और ईरानी जेलों में बंद ब्रिटिश नागरिकों को रिहा कराने के लिये वार्ता की खातिर सोमवार को पहली बार ईरान का दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था की पिछले सप्ताह आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार ईरान वैश्विक शक्तियों के साथ अपने परमाणु करार की शर्तों का पालन कर रहा है। यह रिपोर्ट ईरान पर अमेरिका के नए सिरे से प्रतिबंध लगाने के कुछ दिन बाद आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से हुए अंतरराष्ट्रीय समझौते से अलग होने के बाद इस्लामी देश पर एकतरफा कई दौर के प्रतिबंध लगाकर तेहरान पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका के तेहरान के साथ परमाणु करार से अलग होने के बाद हंट ईरान का दौरा करने वाले किसी पश्चिमी देश के पहले विदेश मंत्री हैं।

हंट ने लंदन में एक बयान में कहा, ''परमाणु हथियार संपन्न ईरान से खतरे को खत्म कर पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने के लिये तेहरान के साथ एटमी करार महत्वपूर्ण है।'' हंट परमाणु कार्यक्रम संबंधित प्रतिबंधों से राहत कायम रखने के यूरोपीय प्रयासों पर बातचीत के लिये ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जारिफ से मिलेंगे। हंट सीरिया और यमन में चल रहे संघर्ष में ईरान की भूमिका पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही वह हिरासत में लिये गए ब्रिटेन और ईरान की दोहरी नागरिकता रखने वाले नागरिकों के मामलों पर भी चर्चा करेंगे। इनमें नाजानिन जागारी रैटक्लिफ का चर्चित मामला है जो कथित राजद्रोह के लिये पांच साल जेल की सजा काट रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''हम अवश्य देखना चाहेंगे कि ईरान में जेल में बंद निर्दोष ब्रिटिश-ईरानी दोहरे नागरिक ब्रिटेन में अपने परिवारों के पास लौट जाएं।'' उन्होंने कहा, ''इसलिये मैं ईरान में देश के नेताओं के लिये स्पष्ट संदेश के साथ आया हूं कि निर्दोष लोगों को जेल में डालने को कूटनीतिक फायदे के औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये।''

रिपब्लिकन रिक स्कॉट ने फ्लोरिडा सीनेट सीट पर जीत हासिल की

नई दिल्ली (एजेंसी)।

मियामी। अमेरिका में फ्लोरिडा के निवर्तमान रिपब्लिकन गवर्नर रिक स्कॉट ने बिल नेल्सन के साथ कड़ी टक्कर में करीबी अंतर से सीनेट सीट जीत लिया है। रविवार को आधिकारिक अंतिम परिणाम जारी किये गये। 2001 के बाद से तीन बार इस सीट पर जीत हासिल करने वाले नेल्सन को इस बार हार का मुँह देखना पड़ा और दोबारा हुई गिनती में पता चला कि डेमोक्रेट नेलसन, रिपब्लिकन स्कॉट से महज 10,000 मत पीछे रह गये।

स्कॉट ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, ''मैंने अभी-अभी सीनेटर बिल नेल्सन के साथ बात की, जिन्होंने विनम्रतापूर्वक हार को स्वीकार किया और मैंने वर्षों से जन सेवा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।''एक दिन पहले ही, डेमोक्रेट एंड्रयू गिलम ने करीबी अंतर से जीत हासिल की थी। इसके जीत के साथ ही वह सनशाइन प्रांत के पहले अफ्रीकी अमेरिकी गवर्नर बने। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बार-बार फ्लोरिडा के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है लेकिन राज्य और स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि चुनाव में कुछ भी गड़बड़ी होने के कोई सबूत नहीं है। जीत के बाद स्कॉट को अमेरिकी नेताओं ने बधाइयां दी। ट्रम्प ने ट्वीट किया, ''पहले दिन से ही रिक स्कॉट का विश्वास एकबार भी नहीं डगमगाया। वह एक महान गवर्नर थे और फ्लोरिडा के लोगों का प्रतिनिधित्व करने में भी एक बड़े सीनेटर साबित होंगे।''

पुलिस अत्याचार के केस में हार्दिक पटेल की गवाही

अधिकारी ने कहा था आरक्षण चाहिए तो मेरे साथ सोने के लिए आना पड़ेगा

पुलिस ने निर्दोष युवकों की छाती में गोली मारी थी, सत्ता के नशे में डयूटी भूलने वाले दोषीयों को सजा दो: हार्दिक

अहमदाबाद । पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान गत १५.८.२०१५ को शहर के हेल्मेट सर्कल के पास जीएमडीसी ग्राउन्ड में पाटीदारों पर पुलिस अत्याचार के केस में पास के कन्वीनर हार्दिक पटेल सोमवार को घीकांटा कोर्ट में पेश हुए थे । जीएमडीसी ग्राउन्ड पर हुए पुलिस अत्याचार के केस में सोमवार को हार्दिक पटेल ने मेट्रोपोलिटन कोर्ट नंबर-२३ में खुद पेश होकर अत्यंत सनसनी गवाही देने से खलबली मच गई है । हार्दिक पटेल ने पुलिस अधिकारी और पूरे प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि, जीएमडीसी ग्राउन्ड में हुए लाठीचार्ज जलियावाला बाग से कम नहीं है । उस समय में मंच पर आंदोलन करने के लिए आई २८ वर्ष की एक महिला को सेक्टर-१ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव रंजन ने बताया है कि, आरक्षण चाहिए तो मेरे साथ सोने के लिए आना पड़ेगा । हार्दिक की गवाही रिकॉर्ड पर लेने के बाद मेट्रोपोलिटन मेजि स्ट्रेट द्वारा केस की आगे की सुनवाई दिसम्बर महीने में मुकर्र की गई थी ।

जीएमडीसी ग्राउन्ड में पाटीदारों पर पुलिस अत्याचार के केस में पास के कन्वीनर हार्दिक पटेल सोमवार को घीकांटा कोर्ट में पेश हुए थे ।

हार्दिक पटेल ने अपने तरीके से अपनी गवाही में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर सरकारी प्रशासन की पोल खोलते हुए गवाही दी थी। उस समय पुलिस ने किस तरीके से पाटीदार सहित के युवकों और महिलाओं को पुलिस अत्याचार का शिकार बनाया गया था इसकी जानकारी कोर्ट के समक्ष पेश की थी । हार्दिक की गवाही सुनकर एक समय वकील-पक्षकारों सहित सभी आश्चर्य में पड़ गये। हार्दिक ने अपनी गवाही में बताया कि, पाटीदार आरक्षण आंदोलन के तहत वह २५ अगस्त, २०१५ को जीएमडीसी ग्राउन्ड पर आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस समय में २५ अगस्त को सुबह में ७ बजे लाखों लोग वहां पहुंचे थे और ग्राउन्ड में उपस्थित थे । प्रजातंत्र में लोगों की कीमत होती है। प्रजातंत्र देश माना जाता भारत का संविधान लोग बोलने की, आंदोलन करने की मंजूरी देता है। सुबह में १० बजे करीब उपस्थित भारी संख्या में लोगों के सामने ५४ मिनट सामाजिक उत्थान के लिए बात पेश की थी, जबकि मैं मैदान पर आया तब लोग शांतिपूर्ण तरीके से सुन रहे थे। यह सभा थी, जिसके पहले पूरे गुजरात में २०० से ज्यादा रैली और सभा आयोजित की गई थी। सरकार के विरूद्ध युवापीढ़ी अपनी नाराजगी व्यक्त रही थी । लोगों की इतनी बड़ी संख्या होने से हमारी टीम द्वारा निर्णय लिया गया कि, इतना बड़ा जुलूस लेकर कलेक्टर को आवेदनपत्र देने के लिए नहीं जाना है इसी वजह से निर्णय किया कि, हम मैदान पर ही बैठेंगे । इसके बाद हमने मुख्यमंत्री आनंदीबहन पटेल को आवेदनपत्र लेने के लिए मंच पर आये ऐसी मांग की थी और आनंदीबहन हमारा आवेदनपत्र स्वीकार करे इस उद्देश्य से हम दोपहर में दो बजे वापस मैदान पर आये । इसके बाद उपस्थित लोगों की बात मानकर हमने आवेदनपत्र देने के लिए कलेक्टर ऑफिस गये। पूरे गुजरात से आ रहे लोगों की मांग थी कि हार्दिक रैली करना जरूरी है ।

आज तुलसी विवाह के अवसर पर भगवान कृष्ण के फोटो के साथ यात्रा निकाली गई थी ।

किसानों की सहायता के नाम पर नाटक कर रही गुजरात सरकार: कांग्रेस

अहमदाबाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्तसिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि गुजरात की भाजपा सरकार किसानों की सहायता के नाम पर केवल नाटक कर रही है। एक ओर गुजरात में अकाल की स्थिति है, दूसरी ओर समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेचने में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गोहिल ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में किसानों की हालत दयनीय हो गई है। राज्य सरकार पर समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए गोहिल ने कहा कि नाफेड ने गुजरात से खरीदी करने से इंकार कर दिय है। नाफेड ने 15 नवंबर को केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को पत्र लिख गुजरात सरकार पर कई आरोप लगाए। पिछले साल समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंगफली की उचित व्यवस्था नहीं की गई। जिसमें कई गोदामों में आग लगने की घटना सामने आई।

युवक पिछले सात वर्ष से एक तरफी प्रेम में पागल

रेसीडेन्ट महिला डॉक्टर द्वारा युवक के खिलाफ शिकायत

युवक द्वारा अक्सर अश्लील हरकत की जाती थी : आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की खोजबीन

अहमदाबाद । सीविल अस्पताल की रेडियोलोजी विभाग में डयूटी कर रही एक रेसीडेन्ट डॉक्टर युवती को शाहीबाग में रहते एक युवक द्वारा अक्सर अश्लील हरकत द्वारा परेशान किए जाने से महिला डॉक्टर ने पूरे मामले में आरोपी युवक के विरूद्ध और एक बार शाहीबाग पुलिस स्टेशन में शिकायत की है । पुलिस की प्राथमिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि, युवक पिछले सात वर्ष से युवती के एक तरफी प्रेम में पागल है । पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के लिए खोजबीन शुरू की गई है । कुछ समय पहले युवती ने शाहीबाग पुलिस स्टेशन में युवक के विरूद्ध में शिकायत की है तब गत दिन भी इसकी हरकत चालू रहने से और एक शिकायत पुलिस स्टेशन में की है। असारवा की सीविल अस्पताल की रेडियोलोजी विभाग में रेसीडेन्ट डॉक्टर युवती ने शाहीबाग पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ की शिकायत की थी । मूल भूज की और सीविल अस्पताल में पिछले सात वर्ष से अभ्यास करती रेसीडेन्ट डॉक्टर युवती पहले यूएन. मेहता अस्पताल के सामने स्थित ढाबरानगर सोसाइटी में रहती थी । उस समय में सोसाइटी में रहता रवीन्द्र परसोतमभाई परमार युवती को अक्सर देखता था और इसका पीछा करता था । रवीन्द्र इसके प्रेम में इस हद तक पागल हो गया था कि घर की दीवार पर तथा युवती की एक्टिवा पर नाम लिखकर चला जाता था । यह मामले में युवती ने शाहीबाग स्टेशन में संबंधित समय में शिकायत की थी । गति दिन सीविल अस्पताल के कैम्पस में स्थित पीजी. होस्टल में युवती थी उस समय रवीन्द्र होस्टल की लोबी में खड़ा था और इसके सामने देखकर अश्लील इशारा करता था । युवती रवीन्द्र की हरकत से परेशान होकर रुम में चली गई थी और शाम को अपने पति और ननंद को जानकारी दी । युवती के पति ने तुरंत पुलिस शिकायत करने का कहने पर उसने पुलिस कंट्रोल में फोन करके जानकारी देकर शिकायत की थी। शाहीबाग पुलिस ने रवीन्द्र विरूद्ध में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

बीजेपी महिला विंग के द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंति पर लो गार्डन से रैली रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा तक निकाली गई थी ।

दो भाईयों ने संबंधी को मौत के घाट उतार दिया

११ लाख की वसूली में ससुराल पक्ष के रिश्तेदार की निर्मम हत्या

अहमदाबाद। शहर में नये साल से हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। हर एक-दो दिन में अलग-अलग कारणों से हत्या की घटना हो रही है। शहर के राणिप क्षेत्र में गत दिन ११ लाख रुपये की वसूली के मामले में ब्याज पर पैसे लगाने का धंधा करने वाले व्यक्ति की दो भाईयों ने हत्या कर देने से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई । उल्लेखनीय बात यह है कि, मरनेवाला व्यक्ति हत्या करने वाले दोनों भाईयों के ससुरालपक्ष में रिश्तेदार थे और इसके विपरित उन्होंने आरोपी भाईयों को उधार में रुपया दिया था और इसकी वसूली करते थे, इसी वजह से परेशान होकर दोनों भाईयों ने संबंधी को मौत के घाट उतार दिया था। राणिप पुलिस ने पूरे मामले में शिकायत दर्ज करके दोनों आरोपी भाईयों को गिरफ्तार करने के लिए खोजबीन शुरू कर दी है । सुभाषब्रिज क्षेत्र में स्थित हर भोले सोसाइटी में रहते और ब्याज पर पैसे लगाने का धंधा करते हितेशभाई शांतिलाल शाह ने राणीप पुलिस स्टेशन में दो भाईयों के विरूद्ध में हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। हितेशभाई के ५० वर्षीय भाई पंकज शाहपुर में स्थित संकुचित गली में रहता है और ब्याज पर लगाने का तथा शेयरबाजार का धंधा करते है । पंकजभाई अपनी २५ वर्ष की पुत्री के साथ रहते है । २० वर्ष पहले से ही उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई तब से पंकजभाई पुत्री के साथ अकेले रहते है । पंकजभाई के चचेरे भाई मुकेश के मित्र राजुभाई हीराचंद ज ैन, इसके भाई रमेसभाई जैन और पोपटभाई जैन की भतीजी ने दस वर्ष पहले लवमैरिज किया था। पंकजभाई के परिवार में लवमैरिज करने से राजूभाई और पोपटभाई ससुरालपक्ष के थे। राजूभाई को जब भी रुपये की जरूरत होती थी तब वह पंकजभाई के पास से रुपये ले लेते थे । कुछ दिन पहले पंकजभाई ने हितेशभाई को बताया कि राजूभाई उनके पास से ११ लाख रुपये ले गये है।

सरकार द्वारा एक अच्छा और महत्व का निर्णय

राज्य की आंगनवाड़ी के १४ लाख बच्चों को यूनिफोर्म दिए जाएंगे

अहमदाबाद । अहमदाबाद सहित राज्यभर में स्थित ५३ हजार आंगनवाड़ी में लाखों की संख्या में बच्चे खेल के साथ पढ़ाई कर रहे है तब सरकार द्वारा पहली बार राज्य की सभी आंगनवाड़ी के बच्चों को दो जोड़ी यूनिफोर्म दिए जाएंगे । यह योजना देश की पहली योज ना बनी रहेगी। कपड़े के मामले में बच्चों में समानता की भावना रहे और यह आंगनवाड़ी के बच्चे होने का अलग और एक समान पहचान भी रहेगी ।

आंगनवाड़ी के बच्चों लिए सरकार द्वारा अच्छा और महत्व का निर्णय कहा जा सकता है ऐसा निर्णय किया गया है । सामान्य रूप से प्राइवेट प्ले ग्रुप में पढ़ते बच्चों के लिए यूनिफोर्म अनिवार्य होता है। इसी वजह से सभी बच्चे एक समान यूनिफोर्म में अच्छे लगते हैं। प्राइवेट प्ले ग्रुप की तुलना में सरकार की ५३ हजार आंगनवाड़ी में बड़ी संख्या में बच्चे नि:शुल्क प्ले ग्रुप की सुविधा लेते है। सरकारी स्कूलों में यूनिफोर्म की व्यवस्था सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए किया जाता है लेकिन अब आगामी शैक्षणिक वर्ष से आंगनवाड़ी के बच्चे भी प्राइवेट ग्रुप के बच्चे जैसे एकसमान यूनिफोर्म में अच्छे लगेंगे ।

सूत्रों के बताये अनुसार अहमदाबाद सहित राज्य की सभी आंगनवाड़ी की संख्या ५३ हजार है, इसमें ३ से ६ वर्ष के बच्चे प्ले ग्रुप में जाते है । यह बच्चों को सरकार द्वारा आगामी वर्ष से दो जोड़ी यूनिफोर्म दिए जाएंगे । यह बच्चों की संख्या १४ लाख जितनी है, जिसमें लड़कों के लिए चेक्सवाला शर्ट -ब्लू रंग का हाफपेन्ट पसंद किया गया है । जबकि लड़कियों के लिए चेक्सवाली पींक फ्रोक और कोलर तथा स्लिव ब्लू रंग रखा जाएगा । प्रति एक बच्चा एक यूनिफोर्म का औसत खर्च २५० रुपये होंगे । सरकार ने यह योजना के लिए बजट में ३२ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बच्चों को यूनिफोर्म देने के लिए प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है । यह निर्णय की वजह से आंगनवाड़ी में पढ़ते बच्चों के अभिभावकों में खुशी की लहर फैल गई है ।

वर्ल्ड टोइलेट डे अवसर पर गांधी आश्रम के पास टोइलेट कैफे बनाया गया है ।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)